Title : Need to increase customs duty on import of Soyabean and Palm oils to safeguard the interest of indigenous farmers.

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने इस साल के बजट में कई खाद्यान्न पदार्थों पर आयात शुल्क में वृद्धि करके किसानों को बचाने का प्रयास किया लेकिन सोयाबीन, रेपसीड ऑयल एवं केस्टर्ड ऑयल के आयात शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की है जिससे खाद्यान्न तेल का उत्पादन करने वाले किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में राई एवं अन्य तिलहनों का उत्पादन बहुत होता है और उनके परिवार की जीविका इन्हीं खाद्यान्न तेलों पर निर्भर करती है। मेरी जानकारी में आया है कि जैवीकरण के माध्यम से सोयाबीन एवं पॉम ऑयल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। जापान, अमेरिका एवं यूरोप के देश इसे स्वास्थ्य की दृटि से खाना पसन्द नहीं करते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सोयाबीन एवं पॉम ऑयल पर कस्टम डयूटी बढ़ा कर भारतीय किसानों को संरक्षण प्रदान किया जाए।